बैंक का अनुदान और उपयुक्त कोटा नीति उपाय शामिल हैं। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, गलीचा निर्यात संवर्धन परिषद्, भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् और हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से कई संवर्धनात्मक उपाय किए गए हैं जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना, बिक्री-सह-अध्ययन दल और निर्यात बाजारों में जानकारी का प्रसार शामिल है।

हथकरघा के विकास के लिए सहायता

3551. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1991-92 के दौरान हथकरघा के विकास के लिए चालू योजनाओं हेतु राज्यों को पिछले दो वर्षों की तुलना में कम सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) हथकरघा के विकास के लिए इस वर्ष के दौरान राज्य-वार कितनी-कितनी सहायता दिए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) वर्ष 1989 से 1992 के दौरान जारी की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है:—

वर्ष	लाख रुपयों में
1989-90	19610.15
1990-91	19738.12
1991-92	19309.32

(ख) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों और गत वर्षों में हुई प्रगति के आधार पर राशि जारी की जाती है।

(ग) हथकरघा क्षेत्र में राशि का आबंटन राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर योजनावार किया जाता है ना कि राज्यवार। वर्ष 1992-93 के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु प्लान योजनाओं के लिए 4335 लाख रुपये और गैर-प्लान के लिए 21203.40 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए मध्य प्रदेश को धन

3552. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम मिलों के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले श्रमिकों को एन० आर० एफ० योजना के अंतर्गत की गई सेवा के प्रति वर्ष के लिए 1-1/2 माह के हिसाब से अनुग्रह राशि प्रदान किए जाने के संबंध में कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश की अन्य कपड़ा मिलों के श्रमिकों के लिए भी उक्त योजना के अंतर्गत धन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) जी हां। एन टी सी मिलों में लागू स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के अन्तर्गत अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। कर्मचारी द्वारा पूरी की गई सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 1½ माह की परिलब्धियों के बराबर अथवा सेवा निवृत्ति की सामान्य तिथि से पहले सेवा के बकाया महीनों के गुणन के बराबर मासिक परिलब्धियों का इनमें से जो भी कम हो, भुगतान किया जाता है।

(ख) और (ग) जी हां। नोडल मंत्रालय द्वारा ऐसे अनुरोधों पर राष्ट्रीय नवीकरण निधि के मार्गदर्शी ढांचे के भीतर विचार किया जाता है।

Schemes for Promotion of Handloom Sector

3553. SHRI DIGVIJAY SINGH: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government are aware of deteriorating economic condition of handloom weavers in the country;

(b) if so, whether Government have formulated any comprehensive action plan for the promotion of handloom sector during the Eighth Five Year Plan period;

(c) if so, the details thereof;

(d) whether any allocation has been

made for the purpose;

(c) the number of weavers likely to be covered under the scheme;

(f) whether Government have also made any review of the schemes implemented for strengthening of handloom sector during the Seventh Five Year Plan period; and

(g) if so, the details thereof, State-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) while the earning of handloom weavers varies from Season to season depending on the demand and prices of raw materials and finished goods, Government has no specific information that the economic condition of handloom weavers in the country is deteriorating.

.(b) Yes, Sir.

(c) Government has formulated a comprehensive Plan for the development of handloom sector during the Eighth Five Year Plan period. Apart from continuing certain on-going schemes of Seventh Plan which have yielded positive results, the following new schemes have been introduced for implementation during the Eighth Plan period:

1. Margin Money for Destitute Weavers.
2. Project Package Scheme.
3. Group Insurance Scheme.
4. Integrated Handloom Village Development Scheme.
5. Silk Yarn Bank Scheme.

(d) An outlay of Rs. 300.00 crores has been earmarked for implementing the plan schemes during the Eighth Plan period.

(c) While it would not be possible to specify the number of weavers to be covered under the various schemes, it is proposed to extend a number of schemes to weavers outside the cooperative sector also.

(f) Yes, Sir.

(g) The total emphasis in the Seventh Plan and in the earlier Plans had been on reaching across the weavers through cooperative societies and or through handloom development corporations. Since, it has led to the Limited coverage, some of the schemes of Eighth Plan have been re-designed to cover weavers outside the cooperative fold also, besides introduction of new schemes.

Action Against Cotton Exporting Agents

3554. SHRI RAMSINH RATHWA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some Bombay based cotton agents have exported cotton to other countries instead of Russia;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the names of the agents against whom any action has been taken by Government?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) to (c) Information is being collected.

Demand of higher Quota for cotton export

3555. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that cotton growers in the country have demanded that their export quota should be increased;

(b) if so, what quantity of cotton had been exported from Gujarat during the last three years together with the quantity demanded for export by the cotton growers; and

(c) what steps Government propose to take to ensure that the cotton growers get reasonable price for their produce?